



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

सं. 18/2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

**सा.का.नि. 344 (अ).**—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "फास्फोरिक एसिड-तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड समेत)" [एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है], जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 2809 20 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1010/2012-डीजीएडी, दिनांक 08 नवम्बर, 2013, जिसे दिनांक 08 नवम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर संशोधित दर से लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 33/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, जिसे सा.का.नि. 811 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाई थी।

और जहां कि मैसर्स ग्वांगझी क्वीझो कैपिटल सक्सेस केमिकल कं. लि. (उत्पादक या निर्यातक) ने अपने द्वारा निर्यात किए गए विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन तथा उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से

संदर्भित किया गया है) के नियम 22 के अनुसार समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नए शीपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 15/5/2016-डीजीएडी, दिनांक 09 फरवरी, 2017, जिसे 09 फरवरी, 2017 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उन सभी विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यातकों के अनंतिम आंकलन की सिफारिश की है जिसका निर्यात उपर्युक्त पार्टी ने किया है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक की इसके द्वारा समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है। उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 मार्च, 2017 जिसे सा.का.नि. 249 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत यह अधिसूचित किया है कि मैसर्स ग्वांगझी क्वींझो कैपिटल सक्सेस केमिकल कं. लि. (उत्पादक या निर्यातक) के द्वारा किए गए विषयगत माल के सभी निर्यातों का तब तक अनंतिम आंकलन किया जाता रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

और जहां कि मैसर्स ग्वांगझी क्वींझो कैपिटल सक्सेस केमिकल कं. लि. ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 2017 के पत्र (जो कि उनके विधिक प्रतिनिधि मैसर्स एपीजे-एस.एल.जी. लॉ ऑफिसेस् के द्वारा दायर) के तहत नए शीपर रिव्यू के आवेदन को वापस ले लिया है और इस दृष्टि से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत किसी एकल निर्धारण को न करने का निर्णय लिया है और अधिसूचना संख्या 15/5/2016-डीजीएडी, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के तहत नए शीपर रिव्यू को समाप्त कर दिया है। अतः अधिसूचना संख्या 33/2013-सीमा शुल्क-(एडीडी), दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 बिना किसी परिवर्तन के सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर लागू होगी।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 मार्च, 2017 जिसे सा.का.नि. 249 (अ) दिनांक 15 मार्च, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/70/2018-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2018

No. 18/2018-Customs (ADD)

**G.S.R. 344(E).**—Whereas, in the matter of import of Phosphoric Acid-Technical Grade and Food Grade (including Industrial Grade) [hereinafter referred to as the subject goods], falling under the sub-heading 2809 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), the designated authority, vide its final findings in notification

No.15/1010/2012-DGAD, dated the 8th November, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 8th November, 2013 had recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on modified rates on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject country;

And Whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, vide, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.33/2013- Customs (ADD), dated the 31st December, 2013, published vide number G.S.R. 811(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 31st December, 2013;

And Whereas, M/s. Guangxi Quinzhou Capital Success Chemical Co. Ltd. (producer or exporter) have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, vide new shipper review notification No.15/5/2016-DGAD, dated the 9th February, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 9th February, 2017, has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated party till the completion of the review by it. On the basis of above findings, Central Government had notified the provisional assessment of all exports of the subject goods made by the M/s. Guangxi Quinzhou Capital Success Chemical Co. Ltd. (producer or exporter) till the completion of the review, vide, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017- Customs (ADD) dated 15<sup>th</sup> March, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 249 (E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2017;

And Whereas, M/s Guangxi Qinzhou Capital Success Chemical Co. Ltd. through letter dated the 10<sup>th</sup> November, 2017 (filed through their legal representative M/s APJ-SLG Law offices) have withdrawn their application for New shipper review and in view of this, the designated authority decided not to carry out any individual determination under rule 22 of the said rules and terminated the New shipper review vide notification No. 15/5/2016-DGAD, dated the 23<sup>rd</sup> November, 2017 and therefore, the notification No. 33/2013- Customs (ADD) dated the 31st December, 2013 will apply to all concerned producers/exporters without any change.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18, 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017- Customs (ADD) dated 15<sup>th</sup> March, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 249 (E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2017.

[F.No. 354/70/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.